



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

सब के लिए जल, जल के लिए सब: जन, पंचायत और जल जीवन मिशन

13 मार्च 2026

सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइनों, पंपों और भंडारण सुविधाओं जैसी अवसंरचनाओं की जरूरत होती है। इस्पात और कंक्रीट के इन नेटवर्कों के अलावा जल प्रणालियों को हर रोज चालू रखने के लिए इन्हें संभालने वाले लोग भी चाहिए होते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, प्रशिक्षित स्वयंसेवी और तकनीकी कर्मी एक साथ मिल कर स्थानीय जल आपूर्ति प्रणालियों का संचालन, निगरानी और रखरखाव करते हैं। इस तरह, वे ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति में सहायता करते हैं।

जल जीवन मिशन की शुरुआत अगस्त 2019 में की गई। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को घर में नल के कनेक्शन के जरिए सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के समय सिर्फ 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन था। इस मिशन के परिणामस्वरूप 3 मार्च 2026 तक देश भर में 15.82 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पेयजल पहुंचाने के भारत के संकल्प का पता चलता है। इस योजना को 2028 तक बढ़ाते हुए इसके लिए 2026-27 के संघीय बजट में 67670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश भर में ग्रामीण पेयजल अवसंरचना के तेजी से विस्तार में निचले स्तर पर काम करने वाले हजारों व्यक्तियों की कोशिशों का बड़ा योगदान है।

गांवों में ये कोशिशें उन व्यक्तियों की प्रतिबद्धता में प्रतिबिंबित होती हैं जिन पर जल प्रणालियों और उनके कामकाज की निगरानी तथा अपने समुदायों के लिए पानी की गुणवत्ता की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति ने इस तरह के योगदानों की सराहना करते हुए इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को ग्रामीण पेयजल प्रशासन को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए जल महोत्सव 2026 के दौरान पुरस्कृत किया। देश भर में 8 से 22 मार्च तक चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद जल जीवन मिशन के अंतर्गत जन भागीदारी को बढ़ावा देना

है। नीचे वर्णित गाथाएं कुछ व्यक्तियों के प्रयासों की झलक देते हुए अपने समुदाय में ग्रामीण पेयजल सेवाओं के संचालन में उनकी भूमिका की झलक पेश करती हैं।

स्थानीय भागीदारी के जरिए ग्राम जल प्रणालियों का संचालन

उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के मानकुवर गांव में ग्रामीण पेयजल प्रणाली का कामकाज इस बात को दर्शाता है कि स्थानीय भागीदारी ग्रामीण अवसंरचना को चलाए रखने में किस तरह की भूमिका निभा सकती है।



ग्राम प्रधान रचना देवी के नेतृत्व में मऊ ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना ने गांव के सभी 340

परिवारों और 1971 निवासियों के लिए घर में नल के जरिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित की है। अवसंरचना के निर्माण के साथ ही यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं कि प्रणाली लंबे समय के लिए प्रभावी ढंग से काम करती रहे।

गांव का हर परिवार जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए मासिक 50 रुपए का उपयोगकर्ता शुल्क देता है। इस तरह हर महीने जमा होने वाली लगभग 5275 रुपए की रकम का इस्तेमाल प्रणाली की नियमित संचालन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

गांव की जल और स्वच्छता समिति की नियमित बैठकों में बिलिंग, जमा रकम और सेवा आपूर्ति की समीक्षा की जाती है। ये बैठकें जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में पारदर्शिता और सामूहिक निगरानी सुनिश्चित करती हैं। रचना देवी ने समिति में महिलाओं और अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। उनके इस प्रयास से ग्राम स्तर पर समावेशी जल प्रशासन को मजबूती मिली है।

हिमालय की ऊंचाइयों पर जल प्रवाह

लद्दाख के लेह जिले में हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे माथो गांव में एक भरोसेमंद पेयजल प्रणाली को चलाए रखने के लिए लगातार तकनीकी प्रयासों तथा स्थानीय संस्थाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की जरूरत होती है।



लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के लाइनमैन त्सेरिंग दोर्जे ने माथो में ग्राम पेयजल अवसंरचना की स्थापना और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र और मौसम की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में काम करते हुए यह सुनिश्चित करने में योगदान किया है कि गांव के परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत भरोसेमंद पेयजल कनेक्शन

मिल सके। स्थानीय समुदाय के सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से गांव में पेयजल सेवाओं के विस्तार और संचालन में मदद मिली है। इस मिसाल से जाहिर होता है कि किस तरह प्रशासनिक और तकनीकी कर्मों ग्रामीण जल कार्यक्रमों को लागू करने में योगदान करते हैं।

गुजरात में जल गुणवत्ता की रक्षा करती महिलाएँ

गुजरात के नवसारी जिले के गणदेवी तालुका के मानेकपुर गाँव में, ग्राम जल गुणवत्ता टीम की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। ग्राम जल गुणवत्ता टीम की सदस्य फाल्गुनीबेन संजयभाई राठौड़, जल जीवन मिशन के तहत गाँव के घरों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 'फील्ड टेस्ट किट' का उपयोग करके नियमित रूप से पीने के पानी की जांच करती हैं।

पिछले तीन महीनों में, उन्होंने गाँव की सभी बस्तियों के घरों से नमूने एकत्र करने को सुनिश्चित करते हुए, पानी के 19 नमूनों की जाँच की। जाँच के साथ-साथ, समुदाय के भीतर पानी की गुणवत्ता और कीटाणुशोधन के तरीकों (जैसे कि घर पर क्लोरीन से पानी साफ करना) के बारे में जागरूकता गतिविधियाँ भी बढ़ाई जा रही हैं, ताकि स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने में मदद मिल सके।



वह यह भी सुनिश्चित करती हैं कि जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों को समुदाय के साथ साझा किया जाए। यदि पानी की गुणवत्ता को लेकर कोई चिंता या समस्या होती है, तो स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रयोगशाला में परीक्षण के माध्यम से नमूनों का सत्यापन किया जाता है। ग्राम पंचायत की एक निर्वाचित सदस्य होने के नाते, फाल्गुनीबेन 'भुलकू महिला बचत मंडल' स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं और गाँव में आशा कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य

करती हैं, जिससे वह सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक एकजुटता में अपना योगदान दे रही हैं।

जल गुणवत्ता की निगरानी और सामुदायिक भागीदारी में अपनी सक्रियता के माध्यम से, वह गाँव में सुरक्षित पेयजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में योगदान दे रही हैं।

सिक्किम में सामुदायिक नेतृत्व आत्मनिर्भर जल प्रबंधन को बढ़ावा दे रहा है

सिक्किम में, दो महिला सरपंचों ने गाँवों को आत्मनिर्भर जल प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद की है। जब सरकार की ग्रामीण नल-जल पहल उनके गाँवों तक पहुँची, तो शीला सुब्बा और पुष्पा सिंतुरी इस प्रयास में शुरू से ही शामिल हो गईं और उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया।

उन्होंने अपने गाँवों के घरों और वार्डों का दौरा किया, स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी के महत्व तथा सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में समझाया। जैसे-जैसे गाँव वाले चर्चाओं और योजना बनाने



में शामिल होते गए, उनमें इस व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर एक साझा समझ विकसित हुई। इससे घरों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का योगदान करना आसान हो गया, जिससे गाँवों को अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिली।

दारांमदीन ब्लॉक के अंतर्गत रुम्बुक जीपीयू में, सरपंच शीला सुब्बा ने ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। नियमित बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, गाँव वाले योजना बनाने और रखरखाव की गतिविधियों में भाग लेते हैं। आज, सभी घरों के साथ-साथ स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध हैं। सामुदायिक भागीदारी से जल आपूर्ति के सुचारु संचालन और किसी भी प्रकार के व्यवधान के तुरंत समाधान में भी मदद मिलती है।

अपर थाम्बोंग जीपीयू में, सरपंच पुष्पा सिंतुरी ने ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की वित्तीय संवहनीयता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ के परिवार नियमित रूप से 'उपयोगकर्ता शुल्क' का योगदान देते हैं और एकत्र की गई धनराशि का उपयोग रखरखाव और मरम्मत के लिए पारदर्शी तरीके से किया जाता है। अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, उपलब्ध संसाधनों

के प्रभावी उपयोग और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ, यह गाँव एक विश्वसनीय पेयजल प्रणाली बनाए रखने में सफल रहा है।

गाँवों तक नल के पानी की पहुँच का विस्तार

झारखंड की कंचनपुर ग्राम पंचायत में, मुखिया पंकी राणा के नेतृत्व में ग्रामीण पेयजल की पहुँच का विस्तार करने के प्रयास कई गाँवों तक पहुँच चुके हैं।



उनके कार्यकाल के दौरान, पंचायत ने कई बस्तियों में शत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन पहुँचाने का लक्ष्य हासिल किया। इस विस्तार के तहत कंचनपुर गाँव के 670 परिवारों, हेथलाग के 384 परिवारों और गोविंदपुर के 357 परिवारों तक नल का पानी पहुँचाया गया।

इस उपलब्धि के साथ, पंचायत को 'हर घर जल पंचायत' के रूप में मान्यता दी गई, जो इन गाँवों में पाइप से पीने के पानी को पहुँचाने के सफल विस्तार को दर्शाता है। इसके साथ ही, परिवारों को नियमित रूप से उपयोगकर्ता शुल्क देने के लिए प्रोत्साहित करने के भी प्रयास किए गए हैं। इस योगदान से समय के साथ जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव में सहायता मिलती है।

सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण जल प्रणालियों को बनाए रखना

लद्दाख, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण पेयजल प्रणालियों का कामकाज किस तरह बुनियादी ढांचे और स्थानीय भागीदारी की मिली-जुली ताकत पर निर्भर करता है। 'जल जीवन मिशन' के तहत तैयार किए गए बुनियादी ढांचे के साथ-साथ, ग्राम पंचायतों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, महिला समूहों, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और तकनीकी कर्मियों की भागीदारी भी गाँव के स्तर पर इन प्रणालियों के रोज़ाना के कामकाज में योगदान देती है। इस तरह की भागीदारी के माध्यम से, समुदाय ग्रामीण जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के संचालन, रखरखाव और निगरानी में सहायता करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरे देश में घरों तक स्वच्छ पेयजल लगातार पहुँचता रहे।

संदर्भ

जल शक्ति मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2236518®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2236669®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2237015®=3&lang=1>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एसके